

जलवायु परिवर्तन - अपने स्वरूप में लाइये परिवर्तन



teri

The Energy and Resources Institute



Ministry of Environment and Forests

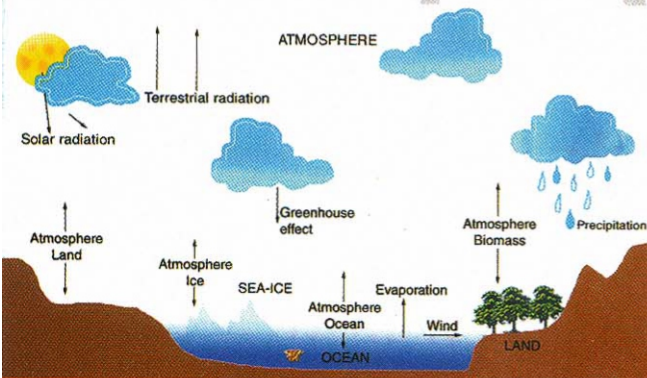
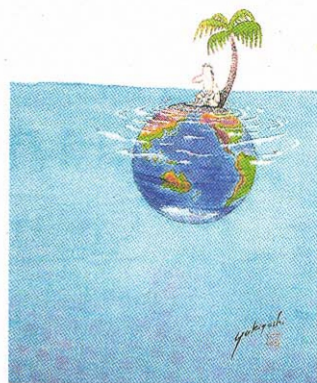
अक्सर कहा जाता है कि जलवायु वह है, जिसकी हम आशा करते हैं और मौसम वह है जो हमें मिलता है। मौसम में बदलाव को हम अपने दैनिक जीवन में महसूस करते हैं, परंतु जलवायु परिवर्तन में कुछ अधिक समय लगता है। जलवायु वास्तव में समय के एक निश्चित अंतराल में एक जगह का औसत मौसम है।

जलवायु परिवर्तन एक विशेष क्षेत्र अथवा इलाके के ही औसत मौसम में बदलाव है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो करोड़ों वर्षों से चली आ रही है—कभी बर्फीले युग तो कभी उष्ण काल। धरती की जलवायु में प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे परिवर्तन होता है और हर तरह के जीवधारी इस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं।

पिछले करीब 150 वर्षों में यह परिवर्तन कुछ अधिक तेजी से हो रहे हैं, इससे वैज्ञानिक और मौसम विशेषज्ञ चिंतित हैं। परिवर्तन की गति में यह तेजी मुख्यतः मानवीय गतिविधियों के कारण हो रही है। इसमें ग्रीनहाउस प्रभाव की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मानवीय गतिविधियों जैसे कि प्राकृतिक ईंधन जलाया जाना, जंगलों का कटना व कृषि के कारण ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा में इतनी वृद्धि हुई है, जो इन गैसों के प्राकृतिक प्रबंधन की क्षमता से कहीं अधिक है। यह परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, इस से कई प्रजातियों को अपने को बदली जलवायु के अनुकूल ढालने का समय नहीं मिल पा रहा है और वे लुप्त हो रही हैं। समुद्र स्तर में वृद्धि, बाढ़ व सूखे में बढ़ोतरी और ऋतु के बदलाव के रूप में जलवायु में परिवर्तन का मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है।

जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को पहली बार जून 1992 में ब्राजील में रियो दि जिनेरो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में उठाया गया। यह एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन था, क्योंकि पहली बार विश्व का ध्यान इस तथ्य पर केन्द्रित था कि पर्यावरणी स्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ, गरीबी और सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान पांच बड़े समझौते किए गए—इनमें से एक यूएनएफसीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा कन्वेंशन) था। इस निकाय का गठन जीएचजी गैसों के निकास स्तर को कम करके स्वीकार्य स्तरों पर लाकर जलवायु परिवर्तन को रोकने की कोशिश के लिए किया था। भारत ने

1992 में यूएनएफसीसीसी पर हस्ताक्षर किए थे, परंतु अधिकतर विकासशील देशों की ही तरह भारत पर भी जीएचजी स्तरों को कम करने की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि विश्व के जीएचजी निकास में उसका योगदान बहुत कम है।

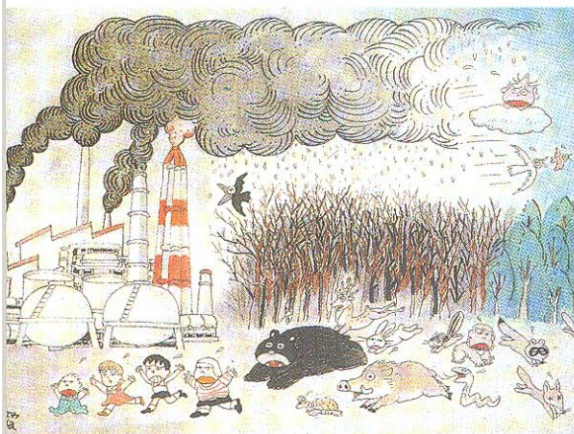


यू.एन.एफ.सी.सी.सी. पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की वर्ष में एक बार सभा होती है जिसमें इसे लागू करने के काम की प्रगति की समीक्षा की जाती है और इसे बढ़ावा देने के प्रयास किये जाते हैं। पार्टियों का प्रथम सम्मेलन (सीओपी-1) 1994 में बर्लिन में हुआ था। तीसरा पार्टी सम्मेलन (सीओपी-3) 1997 में जापान में क्योटो में हुआ जिसके परिणामस्वरूप ऐतिहासिक क्योटो संधि पर हस्ताक्षर हुए। क्योटो संधि में औद्योगिक देशों से जीएचजी निकास में खासी कटौती करने की मांग की गई। अमेरिका ने, जो कि जीएचजी का सबसे अधिक निकास करने वाला देश है, इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। उसे इस बात पर भी आपत्ति थी कि इस संधि में विकासशील देशों पर बाध्यता लक्ष्य लागू नहीं किए गए थे।

पार्टियों के आठवें सम्मेलन (सीओपी-8) का मेज़बान भारत था। 23 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2002 तक विज्ञान भवन में हुए इस सम्मेलन में 180 देशों के 4000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। (सीओपी-8) में इन बिन्दुओं पर सहमति हुई :

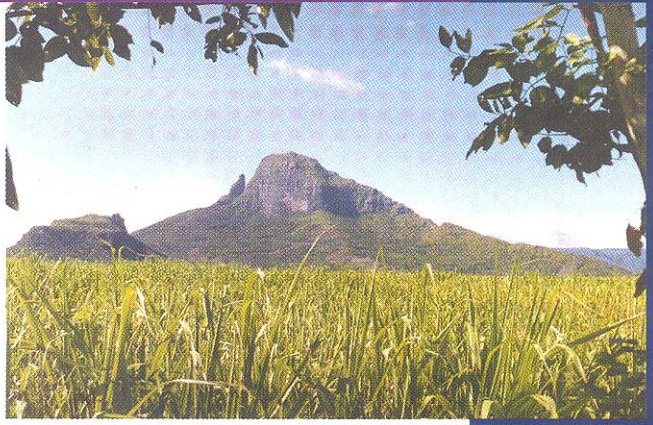
1. विकसित देशों द्वारा जीएचजी निकास आंकड़ों की समीक्षा और रख रखाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
2. अल्पविकसित देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
3. सीओपी-9 के पश्चात् जलवायु परिवर्तन कोष को संस्थानात्मक स्वरूप देना।
4. लोगों को इस मुद्दे पर जागृत करने के लिए शिक्षा व प्रशिक्षण का विश्व व्यापी कार्यक्रम शुरू करना।

विश्व स्तर पर तुरन्त कार्यवाई की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का अन्तरंग सम्बन्ध उन कारकों से है, जो किसी भी राष्ट्र के कल्याण को सीधे प्रभावित करते हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस शिखर सम्मेलन की उच्चस्तरीय बैठक के दौरान इस समस्या के परिमाण को बताया, "भोजन और पौष्टिकता की उपलब्धता सभी के लिए



जी ने ठीक ही कहा है, "आप स्वयं वह बदलाव बनिए, जो आप विश्व में देखना चाहते हैं।"

प्राथमिकता वाले मुद्दे हैं। कृषि का स्थायित्व अनुकूलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। दूसरा जल संरक्षण है। पिछले कुछ दशकों में मौसम से संबंधित आर्थिक क्षतियों और मौतों में काफी वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में भारी उतार-चढ़ाव ज्यादा तेजी से और ज्यादा उग्र रूप से होने लगे हैं, इनसे निपटने की विकासशील देशों की क्षमता को मजबूत किया जाना आवश्यक है।



हम सभी जानते हैं कि हमारा एक ही साझा वातावरण है और हमारे पास केवल एक ही ग्रह है, जिस पर हम जी सकते हैं, इसलिए विश्व नागरिकों के रूप में हमारी यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि इसे साफ रखें और इसको सावधानी से पोषित करें। हालांकि समस्या गंभीर है लेकिन हम व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर ग्रीनहाउस गैसों के निकास को कम करने की कोशिश कर सकते हैं और इस तरह जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से निपट सकते हैं। आइए, जी जान से इसमें जुटें और एक बेहतर भविष्य के लिए कार्य करें।





teri

जलवायु परिवर्तन के बारे में बाल घोषणापत्र 23 अक्टूबर, 2002 नई दिल्ली

पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी-8) के आठवें सत्र में जलवायु परिवर्तन पर
संयुक्त राष्ट्र ढांचा कन्वेंशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

भारत के हम युवा नागरिक बहुत चिंतित हैं क्योंकि—

- मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि हो रही है जिससे विश्व भर में तापमान बढ़ रहा है
- समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण पारिस्थितिकी कुप्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक क्षति हो रही है और तटों पर रहने वाले लोग बेघर हो रहे हैं, और
- वनस्पतियों और जीव जन्तुओं के लिए खतरा बढ़ रहा है और कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्थाओं में जीवनयापन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

हम समाधान की निम्नलिखित कार्यवाहियों की प्रभाविता के बारे में सहमत हुए हैं

- ऊर्जा संरक्षण, साफ ईंधनों और सरकारी परिवहन का प्रयोग
- व्यक्तिगत प्रयासों और लोगों में जागरूकता ला कर जंगल लगाए जाने को प्रोत्साहन
- लोगों को पुनः प्रयोग में लाए जाने वाले ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग की आवश्यकता के बारे में सचेत करना

हम, अपने स्तर पर इस पर्यावरण सहज दृष्टिकोण का भरसक प्रचार प्रसार करने का संकल्प लेते हैं और आज यहां उपस्थित विश्व नेताओं से आग्रह करते हैं कि वे अपने संगठित प्रभाव का अधिकतम उपयोग करते हुए एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षापूर्ण पृथ्वी का अस्तित्व सम्भव बनायें।

Supported by





टेरी ने पर्यावरण और वन मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के सहयोग से सीओपी-8 के दौरान एक अनुषंगी कार्यक्रम के रूप में बच्चों का घोषणापत्र तैयार करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित

की। दिल्ली के 25 विद्यालयों के 125 छात्र-छात्राओं ने इस कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन के मुख्य प्रभावों पर चर्चा की और घर, विद्यालय और अपने पास पड़ोस में ग्रीनहाउस गैसों के निकास में कमी लाने के आसान उपाय सुझाए। घोषणापत्र के माध्यम से बच्चों ने विश्व नेताओं से आग्रह किया कि हमारे लिए पृथ्वी को बचाएं। 30 अक्टूबर 2002 को उच्च स्तरीय बैठक के दौरान यह घोषणा पत्र सीओपी-8 के अध्यक्ष माननीय पर्यावरण और वन मंत्री तिरु टी.आर. बालु को भेंट किया गया।

अधिक जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें :

Environment Education and Awareness Area

TERI

Darbari Seth Block

Habitat Place, Lodhi Road

New Delhi – 110 003

India

Fax 2468 2144 or 2468 2145

E-mail eea@teri.res.in

Tel. 2468 2100 or 2468 2111

Web www.teriin.org/edugreen

India +91 • Delhi 0 (11)